



सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 03 चैत्र, 1943 (श०)
24 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	श्रम संसाधन विभाग	03
(2)	पंचायती राज विभाग	02
(3)	ग्रामीण विकास विभाग	01

कुल योग -- 06

नामांकन एवं केंद्र संचालन प्रारंभ करना

73. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र का चयन सरकार के द्वारा निर्धारित उच्च मानक एवं गाइडलाइन का पालन करते हुये किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्रदाता (के0वाई0पी0) केंद्र वर्ष 2017 से सरकार के बिजनेस पार्टनर के रूप में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देते रहे हैं, परंतु कोरोना के कारण सरकार द्वारा प्रशिक्षण स्थगित करने एवं आर्थिक मदद नहीं दिये जाने के कारण सभी सेंटर की हालत बदतर हो गयी है, वहाँ नया नामांकन के0वाई0पी0 केंद्र को +2 विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद ही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के0वाई0पी0 केंद्र को पूर्व की भाँति नामांकन एवं केंद्र संचालन प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डुप्लीकेट स्टेबलाइजर लगाना

74. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "हर घर नल-जल योजना में लगाये गये बंद कम्पनी के स्टेबलाइजर" के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री हर घर नल-जल योजना में दक्षिणी बिहार के जिलों में मोटर संचालन के लिये जिस कंपनी के स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया गया है वह कंपनी वर्षों पहले बंद हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री हर घर नल-जल योजना में डुप्लीकेट स्टेबलाइजर लगाकर करोड़ों रुपये की अनियमितता की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डुप्लीकेट स्टेबलाइजर लगाकर अनियमितता करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

75. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य द्वारा संचालित कुल 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष 25,000 अभ्यर्थियों का नामांकन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन संस्थानों के प्रशिक्षण के लिये अनुदेशक के 2476 पद रिक्त होने के बावजूद तथा दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक 22 जुलाई, 2020 को बहाली की घोषणा के बाद भी इस पद पर बहाली नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण के लिये अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपाय करना

76. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय 44,652 रुपये है जबकि राष्ट्रीय औसत 1,40,422 रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार राज्य अपने समकक्ष राज्यों की तुलना में सामाजिक संकेतकों में काफी पीछे है, इसलिये राज्य को सामाजिक क्षेत्रों पर दक्षता के साथ अधिक खर्च करना चाहिये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत पर लाने तथा सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक खर्च करने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है ?

मुआवजा व सरकारी नौकरी देना

77. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--हिन्दी दैनिक सामचार-पत्र में दिनांक 9 मार्च, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "स्कूल की बाउंड्री ढही, छह मरे" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 8 मार्च को खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चंडीटोला की चहारदीवारी गिरने से चैधा-बनी गाँव के 6 मजदूरों की मलवे में दबकर मौत हो गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी स्कूल की चहारदीवारी के बगल में 14वीं वित्त योजना के तहत नियमों की अनदेखी कर, जे0सी0बी0 से नाले की खुदाई की जा रही थी और इस दौरान नाले में लगे पाइप कट जाने के कारण पानी बहने लगा, जिससे मिट्टी गीली हो गई और दीवार मजदूरों पर गिर गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने एवं मृतक मजदूरों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

78. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिये एन0सी0पी0टी0, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में Norms बनाया गया था, जिसमें बिहार के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 3 फेज का विद्युत् कनेक्शन तथा ट्रेनिंग के लिये रूम बनाये जाने की बाध्यता थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के अंदर कुल 300 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिन्होंने मान्यता के बाद 3 फेज कनेक्शन नहीं लिया और लगातार बिना बिजली कनेक्शन के कागजात पर ही प्रशिक्षण का संचालन कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैसे संस्थाओं की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 24 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।